भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1011
उत्तर देने की तारीख-10.02.2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर व्यय

1011. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत व्यय करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित नई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने छात्रों हेतु ऑनलाइन शिक्षा मंच के लिए कोई नीति तैयार की है; और
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ .सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ड़):. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में भारतीय लोकाचार पर आधारित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को एक समतापूर्ण और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है, और इस तरह भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाती है। एनईपी 2020 में सभी के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के लाभों का फायदा उठाने के महत्व को स्वीकार किया गया है।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के लिए बजट आवंटन में लगातार वृद्धि सहित कई पहल की हैं, जो वर्ष 2021-22 में 93,224.31 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 1,21,118 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा, "शिक्षा पर बजटीय व्यय 2019-20 से 2021-22 के विश्लेषण" के अनुसार, भारत में शिक्षा पर बजट अनुमान (केंद्र और राज्य) वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.12% है।

भारत सरकार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)/प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को तीन घटकों, अर्थात् "चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाना", "विश्वविद्यालयों को बुनियादी ढांचा अनुदान" और उच्चतर शिक्षा में

सुधार के लिए "बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू)" के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

शिक्षा मंत्रालय आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को भी लागू करता है। इस योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री की पहुँच सुनिश्चित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहायता, शैक्षिक परिसरों का डिजिटलीकरण, वर्चुअल लैब, शोध के लिए ऑनलाइन सामग्री, ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने के लिए तकनीकी सहायता आदि है। प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म स्वयम, साथी, स्वयं प्लस, एफओएस एसईई, इएसएस हैं।

स्वयम एक अत्याधुनिक डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है जो निशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को उच्च-गुणवत्ता, इंटरैक्टिव लर्निंग तक पहुँच प्राप्त हो, जिससे न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा की सुविधा मिलती है। शुरुआत से ही, इस प्लेटफ़ॉर्म ने देश के प्रमुख शिक्षा संस्थानों जैसे आईआईटी और आईआईएम द्वारा क्यूरेट किए गए और वितरित 14,000 से अधिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और इसमें 5 करोड़ से अधिक नामांकन हैं। वर्ष 2024 में, 78 लाख से अधिक नामांकन के साथ 2,557 पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यूजीसी ने 4 सितंबर, 2020 को यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है। इसके बाद, 1 जुलाई, 2021, 18 जुलाई, 2022 और 2 मई, 2024 को संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। यूजीसी ने 108 उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को ओडीएल कार्यक्रम और 99 एचईआई को ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करने के लिए मान्यता/अधिकार प्रदान किया है।

*****